भारत के धन विप्रेषण की बदलती गतिकी - भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि

धीरेंद्र गजभिए, सुजाता कुंडू, अलीशा जॉर्ज, ओमकार विन्हेरकर, युसरा अनीस और जितिन बेबी द्वारा ^

यह आलेख 2023-24 के लिए आयोजित भारत के धन विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणामों का विश्लेषण करता है। प्रमुख निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारत के आवक धन विप्रेषणों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और इसने खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी को पीछे छोड़ दिया है, जो कुशल प्रवासी भारतीयों की ओर प्रवासन स्वरूप में बदलाव को दर्शाता है। महाराष्ट्र, इसके बाद केरल और तमिलनाडु प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य बने हुए हैं। भारत में धन विप्रेषण भेजने की लागत डिजिटलीकरण के कारण वैश्विक औसत लागत से कम है, लेकिन फिर भी 200 अमेरिकी डॉलर के लिए 3 प्रतिशत के सतत विकास लक्ष्य से अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, फिनटेक कंपनियां किफायती सीमा-पार धन विप्रेषण सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे विभिन्न धन विप्रेषण सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

परिचय

भारत का धन विप्रेषण वर्ष 2010-11 के 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 2023-24 में 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के व्यापारिक घाटे[1] के लगभग आधे हिस्से का वित्तपोषण करते हुए, निवल धन विप्रेषण प्राप्तियां इस अवधि के दौरान बाह्य आघातों को अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण साधन रही हैं। इसके अलावा, भारत की धन विप्रेषण प्राप्तियां आम तौर पर भारत के सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह से अधिक रही हैं, जिससे बाह्य वित्तपोषण के एक स्थिर स्रोत के रूप में उनका महत्व स्थापित होता है। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान महामारी-प्रेरित 3.6 प्रतिशत के संकुचन के बाद, महामारी के बाद की अवधि (2021-22 से 2023-24) में भारत में धन विप्रेषण में 14.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ पुनरुत्थान दर्ज किया गया।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख 2023-24 के लिए भारत के आवक धन विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणाम प्रस्तुत करता है।[2] यह भारत में आवक धन विप्रेषण के विभिन्न आयामों को दर्शाता है - देश-वार विप्रेषण का स्रोत, राज्य-वार विप्रेषण का गंतव्य स्थान, लेन-देन के अनुसार विप्रेषण का आकार, अग्रेषण के प्रचलित तरीके, भारत में विप्रेषण भेजने की लागत और नकदी की तुलना में डिजिटल मोड के माध्यम से प्रेषित विप्रेषण का हिस्सा। सर्वेक्षण के परिणाम 30 प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं (परिवार के निर्वाह और बचत[3] के तहत रिपोर्ट किए गए आवक विप्रेषण के कुल मूल्य का लगभग 99 प्रतिशत शामिल करते हुए) पर आधारित हैं। सर्वेक्षण में दो प्रमुख मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ)[4] और दो फिनटेक कंपनियां[5] भी शामिल हैं (ii) रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के कवरेज को एक्सचेंज हाउस/एमटीओ और फिनटेक में वर्गीकृत करना; (iii) धन विप्रेषण आकार ब्रैकेट की सीमा और संख्या का विस्तार करना; (iv) एमटीओ द्वारा किए गए नकद/

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। श्री मनीष कपूर और डॉ. सुनील कुमार की महत्वपूर्ण टिप्पणियों और मार्गदर्शन के लिए लेखक उनके प्रति कृतज्ञ हैं। लेखक, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के प्राधिकृत व्यक्तियों एवं विप्रेषण प्रभाग और बाह्य भुगतान प्रभाग से प्राप्त सुझावों के लिए भी आभारी हैं।

[1] भारत की निवल विप्रेषण प्राप्तियों ने 2010-11 से 2023-24 (महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान वार्षिक औसत आधार पर पण्य व्यापार घाटे के लगभग 42.0 प्रतिशत का वित्तपोषण किया है।

[2] 2020-21 के लिए किए गए सर्वेक्षण के पाँचवें दौर के परिणाम आरबीआई मासिक बुलेटिन के जुलाई 2022 अंक में प्रकाशित हुए। इससे पहले सर्वेक्षण के परिणाम आरबीआई मासिक बुलेटिन के नवंबर 2006, अप्रैल 2010, दिसंबर 2013 और नवंबर 2018 के अंकों में प्रकाशित हुए थे।

[3] विदेशी मुद्रा कारोबार – इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीईआरएस) से संबंधित।

[4] वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इन्कॉर्पोरेशन और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इन्कॉर्पोरेशन

[5] रेमिटली इन्कॉर्पोरेशन और रेमिटबी।

डिजिटल हस्तांतरण को शामिल करना; और v) डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव का आकलन करने के लिए सीमा पार धन विप्रेषण सेवाएं प्रदान करने वाली दो अग्रणी फिनटेक कंपनियों को शामिल करना।

विश्व स्तर पर, आवक धन-विप्रेषण सीमा-पार घरेलू आय के प्रवाह को दर्शाते हैं, जो लोगों के विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में अस्थायी या स्थायी प्रवास से उत्पन्न होता है। इसके अलावा, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ, 2009) द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आँकड़ों में दो मदें धन-विप्रेषण से संबंधित होती हैं - प्राथमिक आय खाते के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति और द्वितीयक आय खाते के अंतर्गत वैयक्तिक हस्तांतरण। भारत के संदर्भ में, वैयक्तिक हस्तांतरण, जिनमें मुख्य रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय श्रमिकों द्वारा परिवार के भरण-पोषण के लिए आवक धन-विप्रेषण और अनिवासी जमा खातों से स्थानीय आहरण शामिल हैं, सीमा-पार आवक धन-विप्रेषण का एक मुख्य हिस्सा बनते हैं।

आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है - भाग II में वैश्विक और भारत के आवक विप्रेषणों के बारे में शोधपरक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। भाग III में भारत में धन विप्रेषण प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों का वर्णन किया गया है। भाग IV में सर्वेक्षण के छठे दौर के निष्कर्षों का विवरण दिया गया है। भाग V में कुछ नीतिगत सुझावों के साथ आलेख का समापन किया गया है।

II. शोधपरक तथ्य

विश्व विप्रेषण के वर्ष 2024 में 905 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) को 75 प्रतिशत से अधिक (लगभग 685 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त होगा [रथ एवं अन्य, 2024]। विश्व बैंक के अनुसार, भारत 2008 से विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है, विश्व विप्रेषण में इसका हिस्सा 2001 के लगभग 11 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 14 प्रतिशत हो गया है। आगे चलकर, भारत में विप्रेषण का उच्च स्तर बने रहने की संभावना है और वर्ष 2029 में इसके लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का पूर्वानुमान है (आरबीआई, 2024)।[6] विप्रेषण के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं (चार्ट 1)। यद्यपि भारत में धन विप्रेषण का प्रवाह महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान थोड़े-बहुत वर्ष-दर-वर्ष संकुचन के साथ सुदृढ़ बना रहा, तथापि

चार्ट 1: सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाले देश

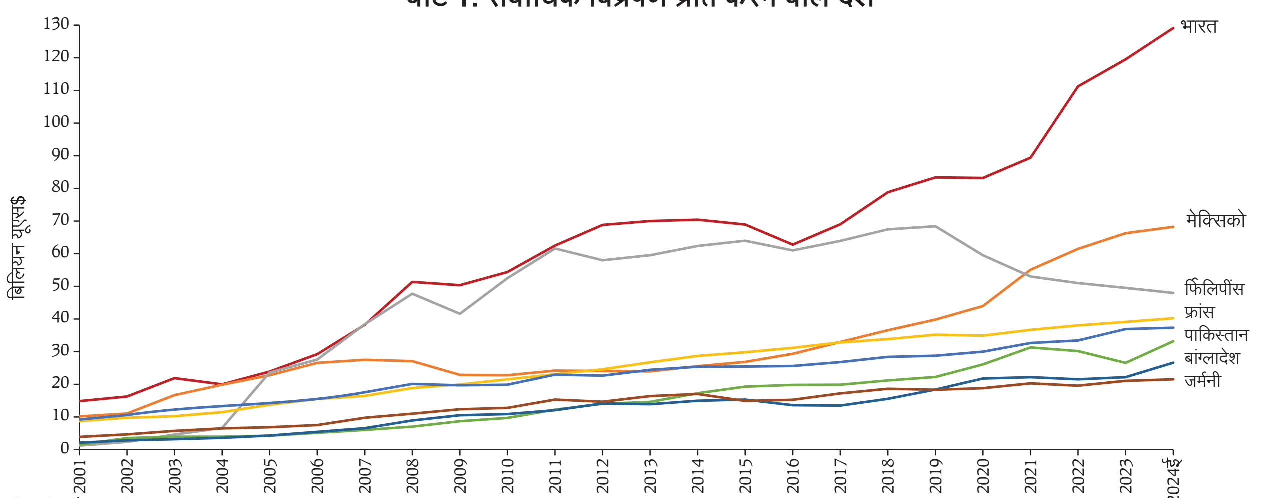

टिप्पणियाँ: 1. ई-अनुमान।
2. अंतर-देशीय तुलना के मामले में, भुगतान संतुलन सांख्यिकी में धन विप्रेषण को प्राथमिक आय खाते के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति और द्वितीयक आय खाते के अंतर्गत वैयक्तिक अंतरण का योग माना गया है।

स्रोत: आरबीआई; और विश्व बैंक।

6 अध्याय 4 - खुली अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण: चुनौतियां और अवसर, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ), 2023-24, आरबीआई।

उसके बाद से इसका पुनरुत्थान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में रोजगार की स्थिति में सुधार से प्रेरित है।

भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 1990 के 66 लाख (6.6 बिलियन) से तीन गुना बढ़कर 2024 में 185 लाख हो गई है और इसी अवधि में वैश्विक प्रवासियों में इसकी हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।[7] खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में भारतीय प्रवासी, दुनिया के कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा हैं (चार्ट 2ए)। सदी की शुरुआत में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और विदेशों में भारतीय आईटी सेवाओं की पहुंच के बाद, उन्नत आर्थिक क्षेत्रों (एई) में, विशेष रूप से अमेरिका में कुशल प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चक्रवर्ती एवं अन्य, 2016; खन्ना एंड मोराल्स, 2023)। इस प्रकार, जीसीसी देशों के अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई) भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में आवक धन विप्रेषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं, जो भारत के प्रवासी समुदाय की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। चूँकि भारत की कार्यशील आयु वर्ग वाली जनसंख्या के वर्ष 2048 तक बढ़ने की उम्मीद है, भारत दुनिया का अग्रणी श्रम आपूर्तिकर्ता होगा (आरबीआई, 2024)। इसलिए, कार्यबल का निरंतर कौशल विकास और पुनर्कौशलीकरण इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जीडीपी के अनुपात के रूप में, भारत का धन विप्रेषण वर्ष 2000 से सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहा है, जबकि चीन के मामले में यह अनुपात 0.3 प्रतिशत से कम बना हुआ है (चार्ट 2बी)। दूसरी ओर, फिलीपींस को पिछले दस वर्षों के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कहीं अधिक धन विप्रेषित हुआ है।

विभिन्न देशों में श्रम के बढ़ते प्रवाह के साथ, कई विकासशील देशों, विशेषकर छोटे देशों, जहाँ ये उनके सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा हैं, के लिए धन विप्रेषण विदेशी आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया है (रथ एवं अन्य, 2024)। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत के संदर्भ में आवक धन विप्रेषण पण्य व्यापार घाटे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का वित्तपोषण करता है (चार्ट 3ए)। इसके अलावा, सदी की शुरुआत से आवक धन विप्रेषण सामान्य तौर पर भारत के सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से आगे निकल गया है और इसलिए यह विदेशी आय का एक स्थिर स्रोत बनकर उभरा है (चार्ट 3बी)।

विप्रेषण की लागत

धन विप्रेषण लेनदेन की लागत में दो तत्व शामिल होते हैं - लेनदेन के किसी भी चरण पर लिया जाने वाला शुल्क और

चार्ट 2: भारत का प्रवासी वर्ग और आवक धन विप्रेषण

ए. भारत के प्रवासी वर्ग की देश-वार हिस्सेदारी

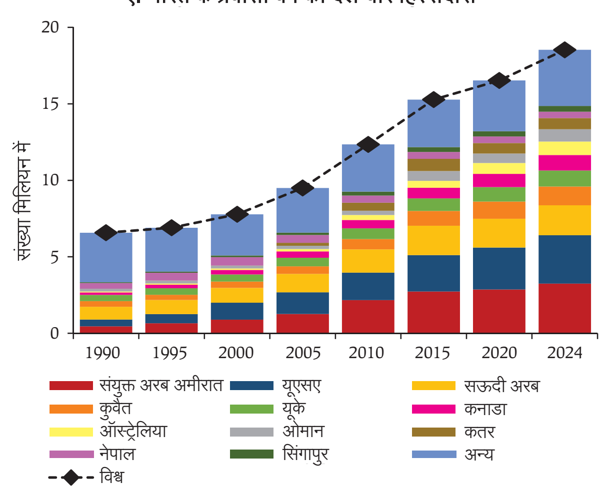

स्रोत: यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स (यूएनडीईएसए)।

बी. आवक विप्रेषण: प्रमुख देश

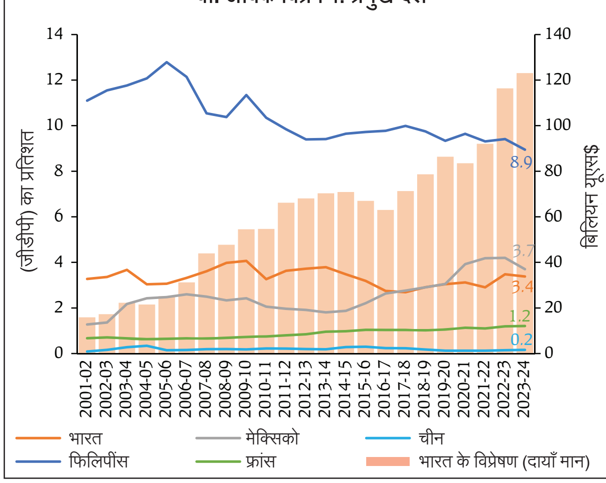

टिप्पणी: भारत को छोड़कर सभी देशों के आँकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर हैं।
स्रोत: आरबीआई; और विश्व बैंक।

[7] डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डेटाबेस (2024), संयुक्त राष्ट्र।

चार्ट 3: भारत का आवक विप्रेषण बनाम पण्य व्यापार घाटा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

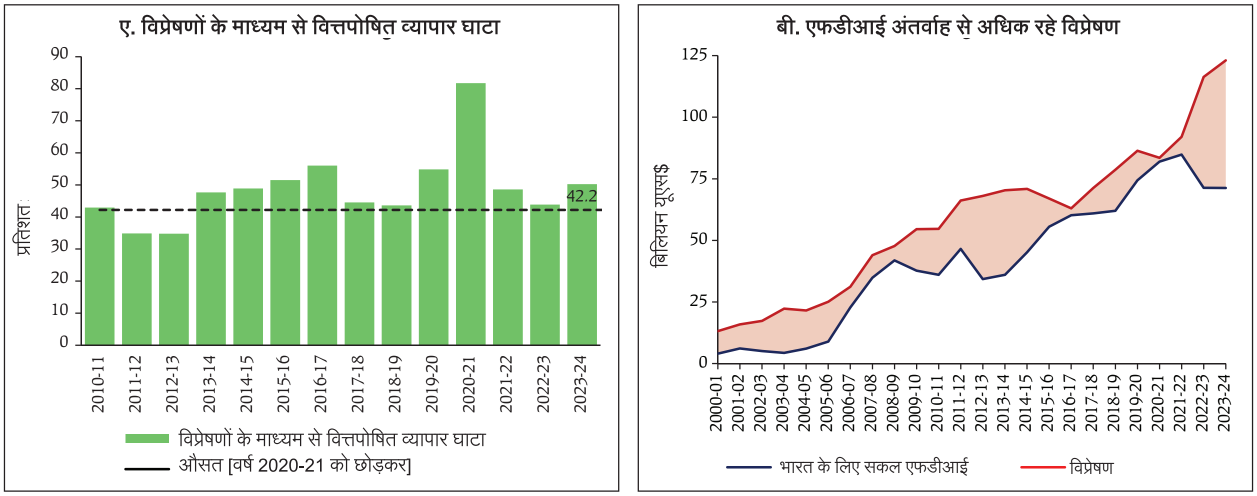

स्रोत: आरबीआई।

स्थानीय मुद्रा से प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा में विनिमय दर रूपांतरण (विश्व बैंक और बीआईएस, 2007)। इस तथ्य को देखते हुए कि आवक धन विप्रेषण बड़े पैमाने पर परिवार के भरण-पोषण के लिए होते हैं, सीमा-पार धन भेजने की लागत का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए, इस लागत को कम करना - एक दशक से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडा रहा है। विश्व बैंक का रेमिटेंस प्राइस वर्ल्डवाइड (आरपीडब्ल्यू) डेटाबेस, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रयोजन की दिशा में प्रगति को मापने के लिए 350 से अधिक कॉरिडोर की निगरानी करता है।[8] 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की वैश्विक औसत लागत में 2009 की पहली तिमाही के 9.67 प्रतिशत से 2024 की दूसरी तिमाही में 6.65 प्रतिशत तक एक निरंतर गिरावट देखी गई, हालाँकि भारत के मामले में यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2023 में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत 4.9 प्रतिशत होने के साथ, भारत में धन विप्रेषण भेजने की लागत न केवल विश्व औसत लागत से कम है, बल्कि धन विप्रेषण लागत की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हुए, प्रारंभिक जी20 लक्ष्य[9] को भी पूरा कर चुकी है। इसके अलावा, भारत 200 अमेरिकी डॉलर भेजने के लिए अल्प लागत वाले देशों में से एक बना हुआ है।

नकद और डिजिटल अंतरण

डिजिटल विप्रेषण की विश्व बैंक की परिभाषा में ऐसे सभी लेनदेन शामिल हैं जिनमें भुगतान ऑनलाइन या स्व-सहायता प्राप्त तरीके से किया जाता है और लेनदेन खाते (बैंक या गैर-बैंक जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्था), मोबाइल मनी या ई-मनी खाते में प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल विप्रेषण का प्रसार तेजी से हुआ है। एमटीओ ने डिजिटल निधीयन और संवितरण को और सक्षम किया है। मोबाइल मनी-सक्षम अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण अंतरण ने वैश्विक स्तर पर महामारी की अवधि के दौरान गति पकड़ी, और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन

[8] प्रवासी धन विप्रेषण की अल्प लागत के महत्व को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में शामिल करने के साथ और भी बल मिला है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रवासी धन विप्रेषण की औसत लागत को 3 प्रतिशत या उससे कम तक लाना और उन कॉरीडोर को समाप्त करना है जहाँ लागत 5 प्रतिशत से अधिक है। लक्षित संकेतक 200 अमेरिकी डॉलर (या स्थानीय विप्रेषण मुद्रा में समतुल्य) भेजने की वैश्विक औसत लागत है, जिसे भेजी गई राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

[9] 2024 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में भारत में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत क्रमशः 5.01 प्रतिशत और 5.02 प्रतिशत रही (विश्व बैंक, 2024)।

चार्ट 4: आवक विप्रेषण भेजने की लागत (200 अमेरिकी डॉलर) - विश्व बनाम भारत

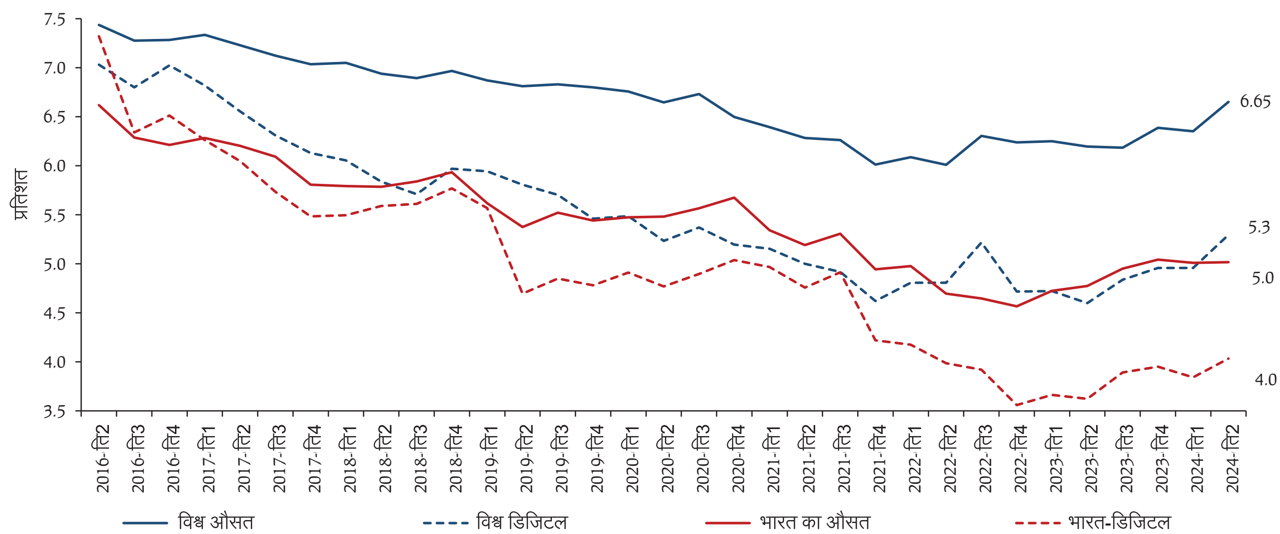

स्रोत: आरपीडब्ल्यू डेटाबेस (2024), विश्व बैंक।

(जीएसएमए) ने अनुमान लगाया कि उनका मूल्य 2019 के 8 बिलियन यूएस$ के दोगुने से अधिक होकर 2021 में 17 बिलियन यूएस$ हो गया, और 2023 में यूएस$ 29 बिलियन हो गया (जीएसएमए, 2024)। डिजिटल धन हस्तांतरण की लागत, जो 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान आरपीडब्ल्यू डेटाबेस में कुल लेनदेन का 30 प्रतिशत थी, 5.3 प्रतिशत थी, जो वैश्विक औसत लागत से 136 आधार अंक कम थी (चार्ट 4)। इसी प्रकार, भारत में डिजिटल धन विप्रेषण की लागत 2024 की दूसरी तिमाही तक 4.0 प्रतिशत थी, जो भारत के 5.0 प्रतिशत की औसत लागत से लगभग 100 आधार अंक कम है, जो धन विप्रेषण लागतों के अनुकूलन में डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह देश और विदेश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करता है। भारत दुनिया भर में अन्य तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को जोड़ने के लिए कई द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के साथ सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के प्रयासों में अग्रणी रहा है और चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के एफपीएस के बहुपक्षीय संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में इसकी भागीदारी है [आरबीआई, 2025]।

III. भारत में आवक विप्रेषण के विभिन्न चैनल

धन विप्रेषण करने वाला देश तीन चैनलों के माध्यम से भारत में धन हस्तांतरित कर सकता है - (i) विदेशी बैंक; (ii) मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ); और (iii) फिनटेक (जिन्हें रेमटेक या केवल डिजिटल एमटीओ[11] भी कहा जाता है) [चार्ट 5]। विदेशी बैंक या तो प्रतिनिधि बैंक का एक नोस्ट्रो खाता बनाये रख सकते हैं या भारत में अपने सहभागी बैंक के साथ एक वोस्ट्रो खाता खोल सकते हैं। धन हस्तांतरित करने का निर्देश सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) मैसेजिंग सेवा या बैंक के अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करके भेजा जा सकता है। प्रतिनिधि बैंक/ सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और

[10] धन विप्रेषण हस्तांतरण में विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियां।

[11] डिजिटल-ओनली एम.टी.ओ. से तात्पर्य ऐसे मुद्रा अंतरण परिचालकों से है जो डिजिटल चैनलों के माध्यम से धन विप्रेषण भेजते हैं (विश्व बैंक, 2024)।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जैसी विभिन्न भुगतान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सकता है। एमटीओ दो योजनाओं के माध्यम से भारत में धन हस्तांतरित करते हैं - मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)[12] और रुपया

चार्ट 5: भारत में आवक विप्रेषण के चैनल - एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व

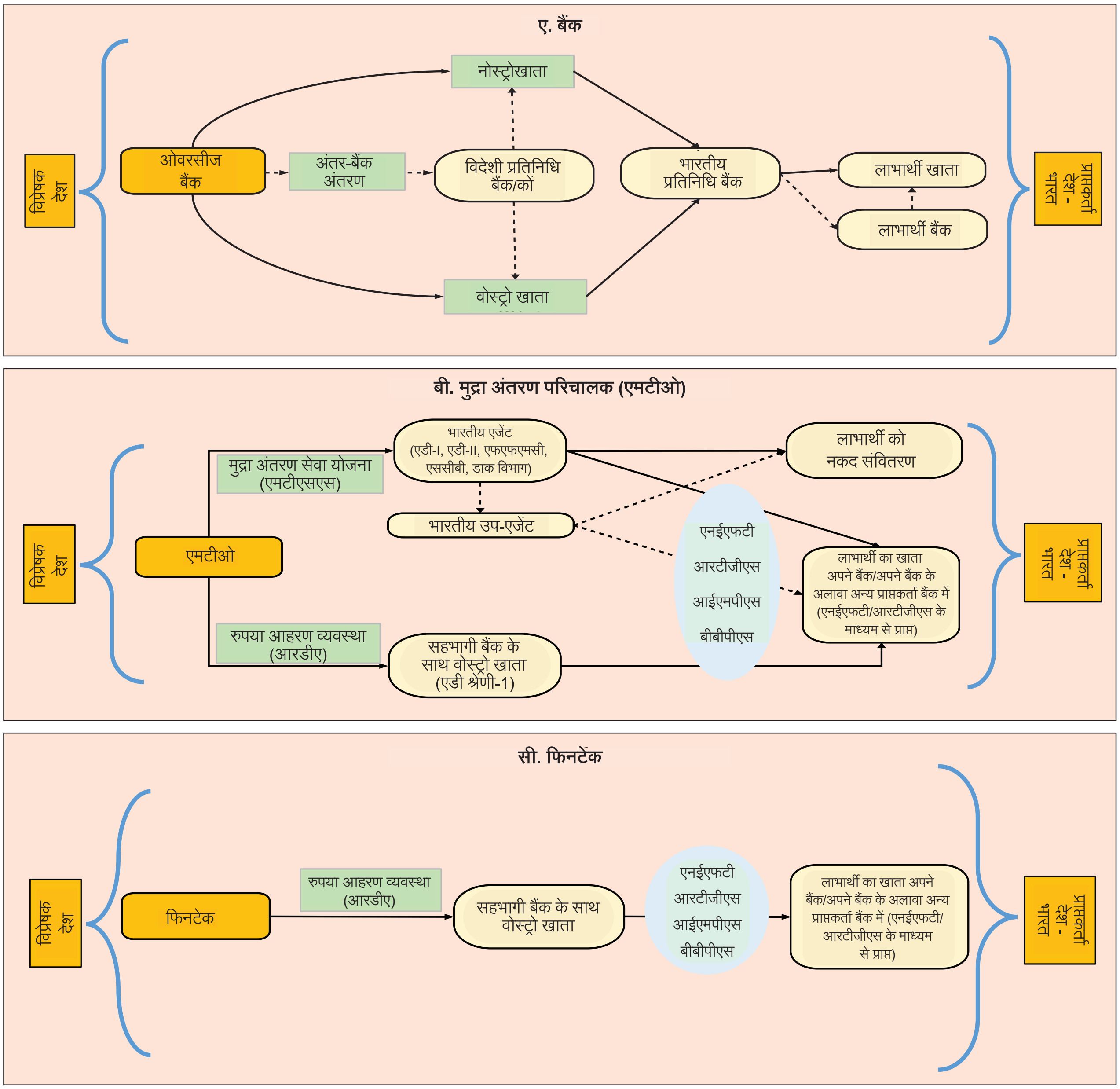

टिप्पणियाँ: 1. एडी-I और एडी-II: प्राधिकृत व्यापारी - क्रमशः श्रेणी I और श्रेणी II: एफएफएमसी: संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और एससीबी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।
2. अंतर-बैंक हस्तांतरण के लिए, विभिन्न बैंकिंग क्षेत्राधिकारों के मामले में नोस्ट्रो/वोस्ट्रो संबंध लागू होते हैं। समान बैंकिंग क्षेत्राधिकारों के मामले में घरेलू भुगतान निपटान का उपयोग किया जा सकता है।
3. पात्र अनिवासी संस्थाओं को एक्सचेंज हाउस के रूप में आरडीए में प्रवेश करने की अनुमति दी गई (आरबीआई, 2022बी)।
4. योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व में एफपीएस की इंटरलिंकिंग के तहत परिकल्पित ट्रांसमिशन चैनल शामिल नहीं है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ चित्रण।

[12] एमटीएसएस में केवल वैयक्तिक धन विप्रेषण अनुमत हैं, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 2,500 अमेरिकी डॉलर और प्रति लाभार्थी सालाना 30 धन विप्रेषण है। व्यापार, संपत्ति खरीद, निवेश या धर्मार्थ दान के लिए धन विप्रेषण निषिद्ध है। इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत विदेशी मुद्रा अंतरण कंपनियों (विदेशी प्रमुख) और घरेलू संस्थाओं (भारतीय एजेंटों) के बीच समझौता शामिल है।

आहरण व्यवस्था (आरडीए)[13], जबकि फिनटेक[14] केवल आरडीए चैनल के माध्यम से ही संचालन कर सकते हैं।[15]

IV. भारत का आवक धन विप्रेषण: सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि

आवक विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर[16] में 30 एडी बैंक (परिवार के भरण-पोषण और बचत के उद्देश्य से रिपोर्ट किए गए कुल आवक विप्रेषण के मूल्य का लगभग 99 प्रतिशत), दो प्रमुख एमटीओ और सीमा पार विप्रेषण कारोबार में कार्यरत दो फिनटेक कंपनियां शामिल थीं। विप्रेषण के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष - विप्रेषण के हस्तांतरण या प्राप्ति के तरीके को बदल रहे हैं।

विप्रेषण का स्रोत

सर्वेक्षण के परिणाम जीसीसी देशों से एई (विशेष रूप से अमेरिका, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो 2023-24 में आधे से अधिक विप्रेषण के लिए जिम्मेदार थे) में भारत के विप्रेषण के प्रभुत्व में क्रमिक बदलाव को उजागर करते हैं। भारत के कुल विप्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही, जो 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 27.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 1), जो अमेरिकी नौकरी बाजार में स्थिर सुधार को दर्शाती है। अमेरिकी श्रम बल में, विदेश में जन्मे श्रमिकों की प्रतिशत वृद्धि 2022 में 6.3 प्रतिशत रही, जो 2019 के महामारी-पूर्व वर्ष में 0.7 प्रतिशत थी; हालाँकि, मूल रूप से जन्मे श्रमिकों के मामले में हिस्सेदारी मोटे तौर पर 1.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।[17] इसके अलावा, अमेरिका में 78 प्रतिशत भारतीय प्रवासी प्रबंधन, कारोबार, विज्ञान और कला व्यवसायों जैसे उच्च आय वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं (ग्रीन और बटालोवा,

सारणी 1: भारत के आवक विप्रेषण में स्रोत देश-वार हिस्सेदारी (बैंक)

स्रोत देश	2016-17	2020-21	2023-24
संयुक्त राज्य	22.9	23.4	27.7
संयुक्त अरब अमीरात	26.9	18.0	19.2
यूनाइटेड किंगडम	3.0	6.8	10.8
सऊदी अरब	11.6	5.1	6.7
सिंगापुर	5.5	2.4	6.6
कुवैत	6.5	1.5	3.9
कतर	–	5.7	4.1
कनाडा	3.0	1.6	3.8
ओमान	1.0	0.6	2.5
ऑस्ट्रेलिया	–	–	2.3
बहरीन	0.7	0.7	1.5
हांगकांग	-	-	1.3
जर्मनी	0.6	0.6	1.0
बेल्जियम	0.9	1.1	0.4
मलेशिया	–	–	0.6
न्यूज़ीलैंड	2.3	0.7	0.5
आयरलैंड	–	–	0.4
नीदरलैंड	–	–	0.5
जापान	–	–	0.3
स्विट्ज़रलैंड	–	–	0.4
फ्रांस	0.1	0.1	0.2
इटली	–	–	0.1
इंडोनेशिया	–	–	0.2
थाईलैंड	–	–	0.2
दक्षिण अफ्रीका	–	–	0.1
स्पेन	–	–	0.1
अन्य	14.8	31.6	4.4

टिप्पणी: 2023-24 के लिए, शेयर आवक विप्रेषण के दो प्रमुख घटकों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं - (क) पारिवारिक भरण-पोषण और बचत हेतु अंतरण; (ख) अनिवासी जमा खातों से स्थानीय स्तर पर आहरण।

स्रोत: 2016-17 और 2020-21 के लिए आँकड़े क्रमशः आरबीआई के विप्रेषण सर्वेक्षणों - आरबीआई (2018) और आरबीआई (2022ए) से प्राप्त किए गए हैं।

[13] आरडीए भारत में एडी श्रेणी-I बैंकों और गैर-निवासी विनिमय प्रतिष्ठान के बीच खाड़ी देशों, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया (केवल स्पीड रेमिटेंस प्रक्रिया के तहत मलेशिया के लिए) और अन्य सभी देशों में अपने रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से सीमा पार विप्रेषण सक्षम बनाता है जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के अनुरूप हैं (केवल स्पीड रेमिटेंस प्रक्रिया के तहत)। हालांकि ऐसे गैर-निवासी विनिमय प्रतिष्ठान विप्रेषण क्षेत्राधिकार में उनके वर्गीकरण के अनुसार फिनटेक भी हो सकते हैं, लेकिन आरडीए योजना में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में फिनटेक की परिकल्पना नहीं की गई है। आरडीए अलग-अलग व्यक्तियों के बीच निजी विप्रेषण की अनुमति देता है, जिसमें व्यापार संबंधी लेनदेन के लिए सीमित प्रावधान हैं, जिनकी सीमा ₹15 लाख है। एमटीएसएस के विपरीत, आरडीए में वैयक्तिक धन विप्रेषण की राशि या आवृत्ति पर कोई सीमा नहीं है और यह केवल आवक हस्तांतरण के लिए है।

[14] फिनटेक कंपनियां जिनके पास संबंधित स्थानीय मौद्रिक/पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस हैं तथा जिनके पास मुद्रा विनिमय/धन हस्तांतरण कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकार/लाइसेंस है।

[15] हाल ही में, आरबीआई एफपीएस को आपस में जोड़ने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। उदाहरण के लिए, यूपीआई-पेनाउ लिंकेज इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सिंगापुर और भारत ने ओपन बैंकिंग एपीआई का लाभ उठाकर संबंधित देशों में भाग लेने वाली वित्तीय संस्थाओं के खाताधारकों को अपने-अपने एफपीएस का उपयोग करके निर्बाध लेनदेन करने की अनुमति दी है। (आरबीआई, 2024)।

[16] शीर्ष धन-विप्रेषण प्राप्त करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आवक धन-विप्रेषणों की संकलन पद्धति का विवरण, साथ ही उनके धन-विप्रेषण सर्वेक्षण, यदि कोई हों, अनुबंध सारणी ए1 में उल्लिखित हैं।

[17] श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, अमेरिकी श्रम विभाग। विदेश में जन्मे श्रमिक: श्रम बल विशेषताएँ।

2024)।[18] यूके से प्राप्त आवक विप्रेषण का हिस्सा भी 2020-21 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.8 प्रतिशत हो गया है, जिसका श्रेय भारत और यूके के बीच 'प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी' (मई 2021) को दिया जा सकता है।[19] प्रत्येक वर्ष यूके जाने वाले भारतीयों की संख्या 2020 के अंत तक 76,000 से तीन गुना से अधिक बढ़कर 2023 के अंत तक लगभग 250,000 हो गई है, जिनमें से लगभग आधे लोग काम से संबंधित उद्देश्य के लिए गए थे।[20] 2023-24 में सिंगापुर (6.6 प्रतिशत), कनाडा (3.8 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (2.3 प्रतिशत) से प्राप्त विप्रेषण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेषकर महामारी वर्ष (2020-21) से तुलना करने पर। हाल के वर्षों में, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। जनवरी 2024 तक, विदेश में पढ़ रहे कुल 13.4 लाख भारतीय छात्रों में से, कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों की हिस्सेदारी 32.0 प्रतिशत थी, इसके बाद अमेरिका (25.3 प्रतिशत), यूके (13.9 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (9.2 प्रतिशत) का स्थान था।[21]

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत के धन विप्रेषण के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसका हिस्सा 2020-21 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गया। यूएई मुख्य रूप से ब्लू-कॉलर नौकरियों में संलग्न भारतीय प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें निर्माण उद्योग का प्रभुत्व है, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग हैं।[22] यह अमेरिका के बिल्कुल विपरीत है जहां भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से सफेदपोश नौकरियों में कार्यरत हैं, इस प्रकार यूएई की तुलना में प्रवासियों की कम संख्या के बावजूद यह अमेरिका से प्राप्त उच्च विप्रेषण का स्पष्टीकरण देता है। जीसीसी देशों (यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन) ने मिलकर 2023-24 में भारत द्वारा प्राप्त कुल विप्रेषण

सारणी 2: भारत के आवक विप्रेषण की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश-वार हिस्सेदारी 2023-24

गंतव्य राज्य	2016-17	2020-21	2023-24
महाराष्ट्र	16.7	35.2	20.5
केरल	19.0	10.2	19.7
तमिलनाडु	8.0	9.7	10.4
तेलंगाना	–	–	8.1
कर्नाटक	15.0	5.2	7.7
आंध्र प्रदेश	4.0	4.4	4.4
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	5.9	9.3	4.3
पंजाब	1.7	3.0	4.2
गुजरात	2.1	3.2	3.9
उत्तर प्रदेश	3.1	3.7	3.0
हरियाणा	0.8	1.2	2.9
पश्चिम बंगाल	2.7	1.4	2.3
राजस्थान	1.2	1.2	1.5
बिहार	1.3	1.4	1.3
उत्तराखंड	0.2	0.7	1.1
गोवा	0.8	1.1	0.9
मध्य प्रदेश	0.4	0.5	0.9
ओडिशा	0.4	0.5	0.6
झारखंड	0.3	1.9	0.4
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.3	0.4
चंडीगढ़	0.2	0.4	0.4
पुडुचेरी	0.2	0.2	0.3
हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.2
असम	0.1	0.2	0.2
छत्तीसगढ़	0.1	0.3	0.1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	–	0.1	0.08
त्रिपुरा	–	1.1	0.04
मणिपुर	–	–	0.03
मेघालय	–	–	0.03
मिजोरम	–	–	0.03
लद्दाख	–	–	0.02
सिक्किम	–	–	0.02
नगालैंड	–	–	0.02
लक्षद्वीप	–	–	0.01
अरुणाचल प्रदेश	–	0.1	0.01
अंडमान और निकोबार	–	–	0.01

टिप्पणियाँ: (i) 2023-24 के लिए, आवक विप्रेषण के दो प्रमुख घटकों के आधार पर शेयर व्युत्पन्न किए गए हैं - (ए) परिवार के रखरखाव और बचत के लिए अंतरण; (बी) अनिवासी जमा खातों से स्थानीय निकासी।
(ii) 2023-24 में, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डेटा प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें सर्वेक्षण के पिछले दौर में 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

स्रोत: 2016-17 और 2020-21 के डेटा क्रमशः आरबीआई (2018) और आरबीआई (2022ए) से प्राप्त किए गए हैं।

[18] https://datausa.io/profile/soc/management-business-science-arts-occupations

[19] https://www.gov.uk/government/news/uk-india-agree-partnership-to-boost-work-visas-for-indian-nationals

[20] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/yearendingdecember2023

[21] लोक सभा अतारांकित (अनस्टार्ड) प्रश्न संख्या-894, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से आँकड़े उपलब्ध हैं।

[22] https://www.news18.com/business/indian-migrant-workers-middle-east-uae-saudi-arabia-oman-kuwait-jobs-8945228.html

में 38 प्रतिशत का योगदान दिया, (कोविड-19 महामारी वर्ष) 2020-21 में दर्ज की गई हिस्सेदारी से अधिक है।[23] महामारी वर्ष के दौरान जीसीसी क्षेत्र से कम धन विप्रेषण का कारण इस क्षेत्र से संविदा प्रवासी श्रमिकों का बड़े पैमाने पर भारत वापस लौटना था।

विप्रेषण का गंतव्य स्थान

वर्ष 2023-24 में राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)-वार धन विप्रेषण स्थलों की ओर रुख करते हुए, महाराष्ट्र को 20.5 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, हालांकि यह 2020-21 (35.2 प्रतिशत) से कम था [सारणी 2]।[24] केरल का स्थान इसके एकदम बाद रहा और इसी अवधि के दौरान इसकी हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 19.7 प्रतिशत हो गई, इसके बाद तमिलनाडु (10.4 प्रतिशत), तेलंगाना (8.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (7.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब से शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले और रोजगार के अवसरों के लिए यहीं रुकने वाले भारतीय छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है, जो भारत के आवक धन विप्रेषण में इन राज्यों की बढ़ती हिस्सेदारी में परिलक्षित होता है। केरल प्रवासन सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2023 में केरल से कुल प्रवासियों में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट बताती है कि छात्रों के प्रवासन स्वरूप में उल्लेखनीय बदलाव आया है और गैर-जीसीसी देशों को गंतव्य के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में छात्र और श्रमिक विदेश जाते हैं।

विप्रेषण: माध्यम और आकार

जैसा कि खंड III में वर्णित है, बैंक विभिन्न तरीकों से धन विप्रेषण प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से आरडीए चैनल की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, इसके बाद विदेशी बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष वोस्ट्रो स्थानांतरण और फिनटेक द्वारा संचालित आरडीए चैनल है (चार्ट 6ए)। प्रेषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैनल का

चार्ट 6: वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के आवक विप्रेषण का पद्धति-वार और आकार-वार संवितरण

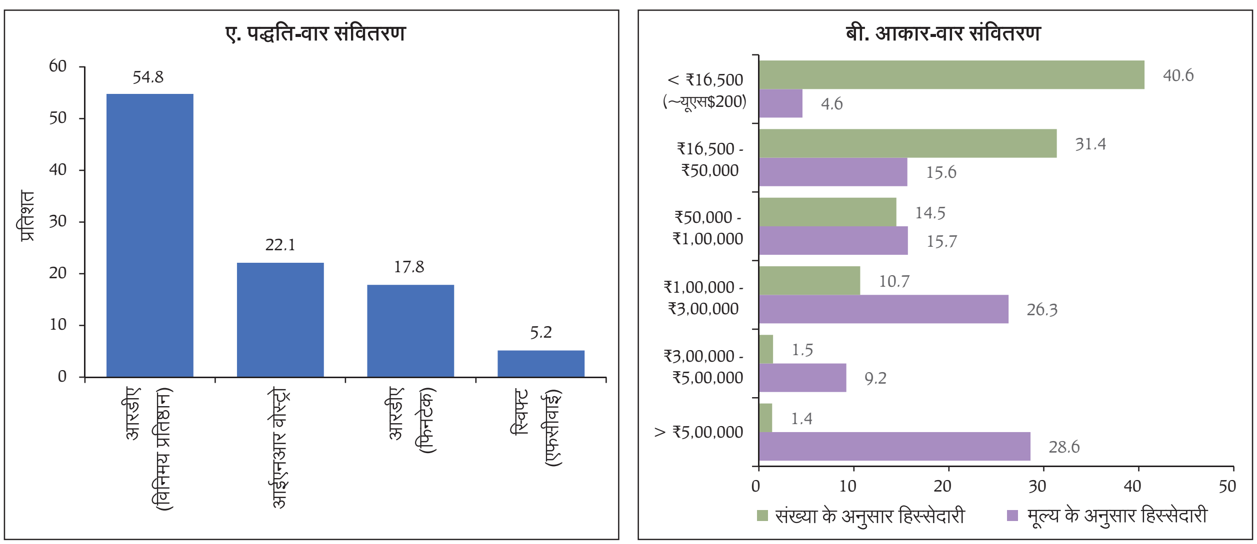

स्रोत: आरबीआई।

[23] सर्वेक्षणों में स्रोत देशों के सामान्य समूह को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 में एई में भारत के आवक विप्रेषण का 51.0 प्रतिशत शामिल था, जबकि जीसीसी देशों का हिस्सा 33.7 प्रतिशत था।

[24] महामारी के कारण हुए भारत में रिवर्स माइग्रेशन के कारण, पारंपरिक विप्रेषण प्राप्तकर्ता राज्यों, जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जो बड़े पैमाने पर जीसीसी देशों पर निर्भर हैं, का हिस्सा 2020-21 में लगभग आधा हो गया, जिससे विप्रेषण में राज्यवार हिस्सेदारी में वितरणात्मक बदलाव आया (आरबीआई, 2022ए)।

चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें औपचारिक बैंकिंग चैनलों की पहुंच, प्रभार और वितरण की गति शामिल है (आईएमएफ, 2009)। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, विनिमय दरों में अंतर के रूप में निहित लागत है। लेनदेन के मूल्य (आकार) के संदर्भ में, ₹5 लाख से अधिक राशि के प्रेषणों की हिस्सेदारी 2023-24 में लगभग 29 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी (चार्ट 6बी)। इसके विपरीत, सबसे अधिक लेनदेन 200 अमेरिकी डॉलर से कम के विप्रेषण आकार की श्रेणी में थे और अधिक मूल्य वाले विप्रेषण की हिस्सेदारी में भी गिरावट का रुझान जारी रहा। चूंकि अधिकांश धन-विप्रेषण अल्प राशि में भेजे जाते हैं, इसलिए 2030 तक 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत को 3 प्रतिशत या उससे कम पर लाने का सतत विकास लक्ष्य महत्वपूर्ण है।

आवक विप्रेषण की लागत

सर्वेक्षण के नवीनतम दौर के अनुसार, यह पाया गया है कि हस्तांतरण के तरीके और धन विप्रेषण के आकार के आधार पर लागत में व्यापक रूप से भिन्नता होती है (चार्ट 7)। भारत में आवक धन विप्रेषण की भारित औसत लागत 200 अमेरिकी डॉलर से कम के लेनदेन आकार के लिए 4.6 प्रतिशत और 200-500 अमेरिकी डॉलर के लेनदेन वर्ग (ट्रांजैक्शन ब्रैकेट) के लिए 2.4 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण में दर्ज सभी लेनदेन वर्गों में 200 अमेरिकी डॉलर से कम की राशि के लिए विप्रेषण की भारित औसत लागत सर्वाधिक थी। इसके अलावा, ब्रैकेट के अंतर्गत प्रतिनिधि बैंकों के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लागत सबसे अधिक थी, उसके बाद वोस्ट्रो खातों के माध्यम से आईएनआर लेनदेन का स्थान रहा। विप्रेषण के आकार के बावजूद, आरडीए (एमटीओ और फिनटेक) के

चार्ट 7: भारत के आवक विप्रेषण की पद्धति-वार और आकार-वार कुल लागत

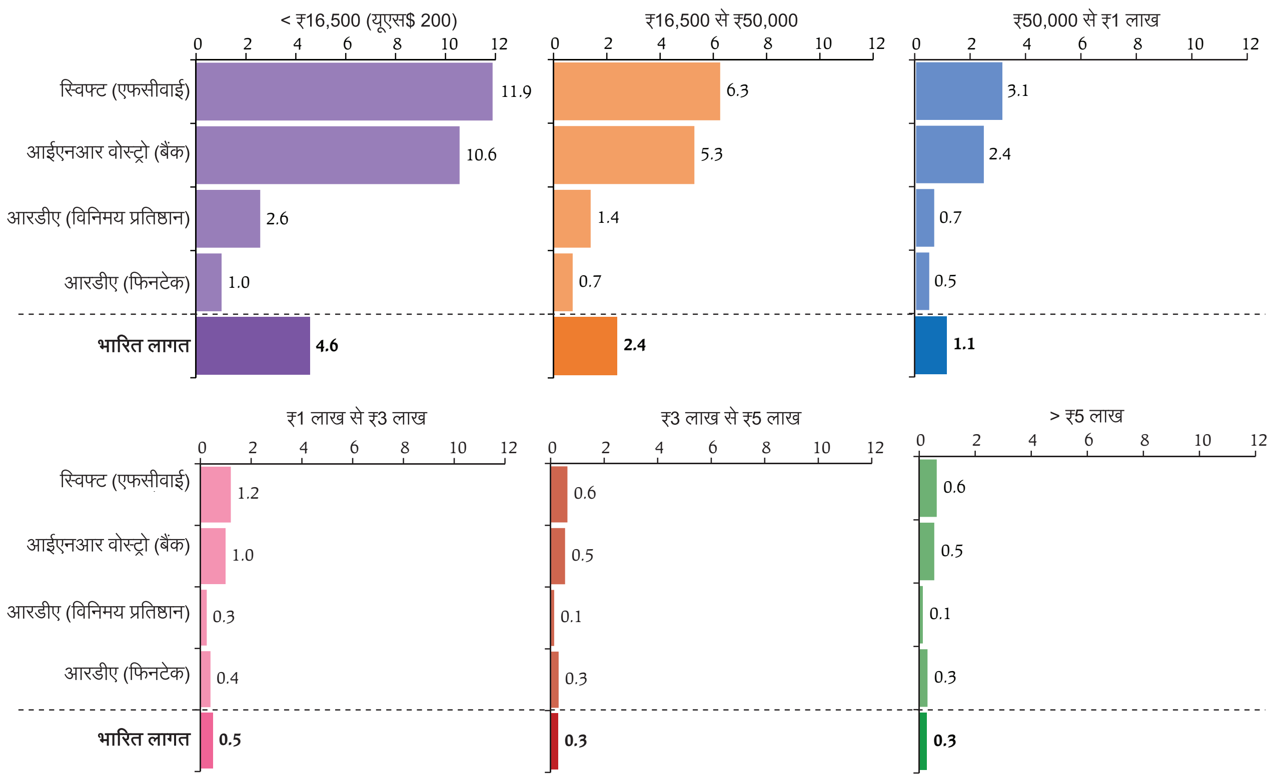

टिप्पणियाँ: 1. आँकड़े, लेनदेन के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कुल लागत को दर्शाते हैं।
2. भारित औसत की गणना प्रत्येक ब्रैकेट के लिए भार के रूप में अंतरण पद्धति (मोड ऑफ ट्रांसफर) के शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 8: विप्रेषणों की नकद-डिजिटल में हिस्सेदारी (एमटीओ)

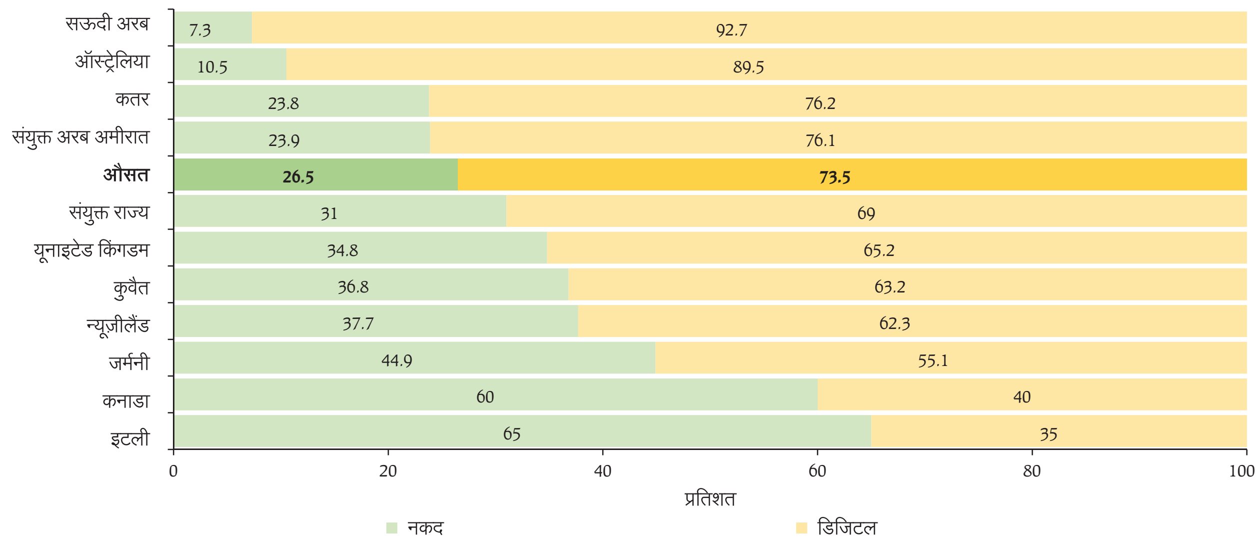

स्रोत: आरबीआई।

माध्यम से विप्रेषण की लागत सबसे कम थी। फिनटेक कंपनियां किफायती सीमा-पार धन-विप्रेषण सेवाएं की पेशकश करती पायी गई हैं, जिससे विभिन्न धन-विप्रेषण सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान सर्वेक्षण दौर में एमटीओ के डिजिटल विप्रेषण लेनदेन का हिस्सा भी शामिल था और यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन कुल विप्रेषण का 73.5 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल मोड के माध्यम से प्राप्त हुआ (चार्ट 8)। विप्रेषण लेनदेन के लिए सर्वाधिक डिजिटल हिस्सा सऊदी अरब (92.7 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया (89.5 प्रतिशत), कतर (76.2 प्रतिशत) और यूएई (76.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

V. निष्कर्ष

भारत के संदर्भ में विप्रेषण ने महामारी के बाद की अवधि में पुनरुत्थान प्रदर्शित किया, जो बाह्य वित्तपोषण के एक स्थिर स्रोत के रूप में उभरा। 2023-24 के लिए भारत के विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणाम, प्रमुख स्रोत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जीसीसी देशों से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत के प्रवासी वर्ग की बदलती गतिकी को उजागर करते हैं। राज्यवार आँकड़ें दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक का स्थान रहा। इसके अलावा, बैंकों के लिए हस्तांतरण के तरीके पर आरडीए चैनल का प्रभुत्व रहा। विप्रेषण भेजने की लागत हस्तांतरण के तरीके और लेनदेन की राशि के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। यह पाया गया कि सर्वेक्षण में दर्ज सभी लेनदेन वर्गों में 200 अमेरिकी डॉलर से कम राशि के लिए विप्रेषण भेजने की भारित औसत लागत सर्वाधिक थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023-24 के दौरान एमटीओ द्वारा प्राप्त कुल विप्रेषण का औसतन 73.5 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल मोड के माध्यम से था। यह, नकद विप्रेषण की तुलना में डिजिटल विप्रेषण की कम लागत के साथ, विप्रेषण परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती पहुँच के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, सीमा-पार तीव्र भुगतान प्रणालियों के आपस में जुड़ने से ऐसे लेनदेन की आसानी और दक्षता बढ़ सकती है। हालाँकि विप्रेषण भेजने की लागत में कमी के संबंध में भारत का निष्पादन उत्साहजनक है, फिर भी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ

उठाने पर एकीकृत नीतिगत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीयों की बदलती गतिकी की संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए, बढ़ते भारतीय कार्यबल के निरंतर कौशल विकास और पुनर्कौशलीकरण की आवश्यकता है।

संदर्भ

Chakravorty, S., Kapur, D. and Singh, N. (2016). The Other One Percent: Indian's in America. Oxford University Press.

Greene, M. and Batalova, J. (2024). Indian Immigrants in the United States. Migration Policy Institute.

GSMA. (2024). The State of the Industry Report on Mobile Money 2024.

IMF. (2009). International Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users. *International Monetary Fund.*

Khanna, G., and Morales, N. (2023). Did US Immigration Policy Influence India's IT Boom? *Economic Brief*, No. 23-42. Federal Reserve Bank of Richmond.

Rajan, S.I. (2024). Kerala Migration Survey 2023. *Kerala Economy.* Vol. 5, No. 3, pp 1-13.

Ratha, D., Plaza, S., and Kim, E. J. (2024). In 2024, remittance flows to low- and middle-income countries are expected to reach $685 billion, larger than FDI and ODA combined. World Bank Blogs, December 18.

RBI. (2018). Globalising People: India's Inward Remittances. *RBI Bulletin* (November).

RBI. (2022a). Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances. *RBI Bulletin* (July).

RBI. (2022b). Master Direction - Opening and Maintenance of Rupee / Foreign Currency Vostro Accounts of Non-resident Exchange Houses (updated as on December 22, 2022).

RBI (2024). Report on Currency and Finance (RCF) 2023-24: India's Digital Revolution.

RBI. (2025). Payment Systems Report.

World Bank. (2024). Remittance Prices Worldwide: Issue 50 (June).

World Bank and BIS (Committee on Payment and Settlement Systems). (2007). General principles for international remittance services. Bank for International Settlements.

अनुबंध

अनुबंध सारणी ए1: आवक विप्रेषणों के संकलन की पद्धति - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष छह देश

क्र. सं.	देश	आवक विप्रेषणों के संकलन की पद्धति	नवीनतम विप्रेषण सर्वेक्षण/विवरण
1	भारत	भुगतान संतुलन के संकलन के लिए धन विप्रेषण के आँकड़े बैंक द्वारा अपनी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे विदेशी मुद्रा लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीईआरएस) कहा जाता है।	https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=21141
2	मेक्सिको	बैंको डी मेक्सिको ने 2012 में वैयक्तिक धन हस्तांतरण के व्यवसाय में शामिल फर्मों (वित्तीय संस्थाओं और धन हस्तांतरण संस्थाओं) के लिए धन विप्रेषण पर डेटा के संकलन के लिए मासिक रिपोर्ट का एक सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।	https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=en
3	चीन	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के भुगतान संतुलन मैनुअल (बीपीएम) में उल्लिखित कार्यप्रणाली और मानकों के आधार पर भुगतान संतुलन डेटा के एक भाग के रूप में राज्य विदेशी मुद्रा प्रशासन (एसएएफई) चीन के विप्रेषण को संकलित करता है।	https://dsbb.imf.org/sdds/dqaf-base/country/CHN/category/BOP00
4	फिलिपींस	भुगतान संतुलन में द्वितीयक आय के अंश वाले धन विप्रेषण को आईटीआरएस के माध्यम से दर्ज किया जाता है तथा सीमापार लेनदेन सर्वेक्षण (सीबीटीएस) द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है।	https://psa.gov.ph/statistics/survey/labor-and-employment/survey-overseas-filipinos
5	पाकिस्तान	स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) का सांख्यिकी और डेटा वेयरहाउस विभाग मासिक आधार पर श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन के आंकड़ों को संकलित और प्रसारित करता है। ये आँकड़े बैंकों, विनिमय कंपनियों और पाकिस्तान डाकघर से एकत्र किए जाते हैं।	https://www.sbp.org.pk/departments/stats/AdvanceNotice.pdf https://easydata.sbp.org.pk/apex/f?p=10:211:18595026959410::NO:RP:P211_DATASET_TYPE_CODE,P211_PAGE_ID:TS_GP_BOP_WR_M,210&cs=1F743692A58FE97CD791417EFAE146503
6	बांग्लादेश	भुगतान संतुलन के संकलन के लिए विप्रेषण के आँकड़े बैंक द्वारा अपनी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।	https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremitance

स्रोत: आरबीआई; आईएमएफ एसडीएसएस; एवं केंद्रीय बैंक वेबसाइटें।